*भारत की अध्यक्षता के दौरान एक बेहतर वैश्विक आर्थिक व्यवस्था के लिए जी-20:**

शक्तिकान्त दास

मुझे खुशी है कि आज मुझे फेडरल बैंक द्वारा के पी होर्मिस स्मृति व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया गया है। फेडरल बैंक के संस्थापक स्वर्गीय श्री के पी होर्मिस एक महान संस्था निर्माता थे, जिन्होंने अर्थव्यवस्था में उद्यमियों की महत्वपूर्ण भूमिका, विशेष रूप से छोटे पैमाने के उद्यमियों को वित्त प्रदान करने में बैंकों के महत्व और वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के लिए बैंकिंग व्यवसाय में विवेक की आवश्यकता को जल्दी पहचाना।

कोविड-19 महामारी, यूक्रेन में युद्ध और दुनिया भर में केंद्रीय बैंकों द्वारा समन्वित सख्त मौद्रिक नीति से वैश्विक अर्थव्यवस्था को लगे कई और अतिव्यापी झटके के बावजूद, भारतीय अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है और दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था होने की उम्मीद है। हमारे वित्तीय क्षेत्र में स्थैर्य बना हुआ है; मुद्रास्फीति का सबसे बुरा दौर हमने पीछे छोड़ा है; और भारतीय रुपये ने अपनी समकक्ष मुद्राओं के बीच सबसे कम अस्थिरता का प्रदर्शन किया है।

जैसा कि आप जानते हैं, भारत ने 2023 के लिए जी 20 की अध्यक्षता संभाली है। भू-राजनीति, व्यापार और आपूर्ति शृंखलाओं में खंडित दुनिया में, भारतीय अध्यक्षता 'वसुधैव कुटुम्बकम: एक पृथ्वी . एक परिवार · एक भविष्य' के दर्शन को घर ले जा रही है। इस दर्शन में भारतीय अध्यक्षता का प्रयास अंतर्निहित क्षमता का एहसास कराना है। इसलिए, मैंने आज अपने संबोधन के लिए "भारत की अध्यक्षता के दौरान एक बेहतर वैश्विक आर्थिक व्यवस्था के लिए जी 20" विषय चुना है।

जैसा कि मैंने कुछ समय पहले कहा था, भारत ने ऐसे विकट भू-आर्थिक बदलावों के माहौल में जी 20 का नेतृत्व संभाला है, जिसने वैश्विक वृहद-वित्तीय परिदृश्य को खराब कर दिया है। कई आघातों के गंभीर प्रभाव का प्रबंधन करने के लिए मौजूदा वैश्विक आर्थिक व्यवस्था की क्षमता चुनौती बनी हुई है। इससे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में गंभीर आपूर्ति-मांग असंतुलन पैदा हो गया है और लगभग सभी देशों में उच्च मुद्रास्फीति को बढ़ावा मिला है। मुद्रास्फीति बहु-दशकीय उच्च स्तर पर पहुंचने और वैश्विक विकास और व्यापार में नरमी ने जटिल नीतिगत चुनौतियां पेश की हैं। वैश्विक समस्याओं के लिए सहयोगात्मक और प्रभावी समाधान को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख मंच के रूप में, आम सहमति बनाने में कठिनाइयों और भू-राजनीति दृष्टिकोण के आसपास अनिश्चितता को देखते हुए जी 20 का कार्य सीमित हो गया है।

मौजूदा वैश्विक संकट जी 20 के लिए एक अवसर और एक प्रमुख परीक्षा दोनों है, जो विश्व जीडीपी के 85 प्रतिशत और वैश्विक व्यापार के 75 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करता है। 1997 के पूर्वी एशियाई वित्तीय संकट के बाद, 1999 में वैश्विक मुद्दों और नीति विकल्पों पर चर्चा करने के लिए वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों के लिए एक मंच के रूप में जी 20 की स्थापना की गई थी। वर्ष 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के बाद, वर्ष 2009 में जी 20 को राज्यों/सरकारों के प्रमुखों के स्तर तक उन्नत किया गया था। एक परस्पर जुड़ी दुनिया में, जब आघातों की प्रकृति वैश्विक और निरंतर होती है, तब अकेले राष्ट्रीय नीतियां पूरी तरह से प्रभावी नहीं हो सकती हैं।

कोविड के बाद, विश्व अर्थव्यवस्था बड़े नीतिगत प्रोत्साहन और टीकाकरण की बढ़ती गति के कारण धीरे-धीरे ठीक हो रही थी, जब यूक्रेन में युद्ध के कारण वैश्विक खाद्य, ऊर्जा और पण्य कीमतों में तेज वृद्धि हुई। इसने नए सिरे से आपूर्ति शृंखला में व्यवधान भी पैदा किया। भू-राजनीति का स्थान अब भू-अर्थशास्त्र ने लिया है । आईएमएफ[1] के अनुसार, वैश्विक अर्थव्यवस्था अब भू-आर्थिक विखंडन की प्रक्रिया का सामना कर रही है, जो पांच प्रमुख चैनलों - व्यापार, प्रौद्योगिकी, पूंजी प्रवाह, श्रम गतिशीलता और वैश्विक शासन के माध्यम से काम कर रही है। व्यापार और प्रौद्योगिकी के प्रसार पर बढ़ते प्रतिबंध, श्रम प्रवासन में बाधाएं, पूंजी प्रवाह में कमी और वैश्विक सार्वजनिक वस्तुओं के बारे में अनिश्चितता बढ़ रही है। भू-राजनीति और राष्ट्रों की आर्थिक

* श्री शक्तिकांत दास, गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 17वां केपी होर्मिस स्मारक व्याख्यान, कोच्चि, 17 मार्च, 2023।

[1] "भू-आर्थिक विखंडन और बहुपक्षवाद का भविष्य," आईएमएफ स्टाफ चर्चा नोट 2023/001।

संभावनाओं के बीच अंतर्संबंध दृढ़ हो गया है, हर एक दूसरे को प्रभावित कर रहा है। अब फ्रेंड-शोरिंग और ऑनशोरिंग का चलन बढ़ रहा है। अब ध्यान खाद्य एवं ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने और रणनीतिक खनिजों - लिथियम, दुर्लभ पृथ्वी तत्व, तांबा, जस्ता, क्रोमियम, ग्रेफाइट आदि को सुरक्षित करने पर है, जो बैटरी, सौर पैनलों और पवन टरबाइन के उत्पादन के लिए आवश्यक हैं।

दरअसल, वैश्वीकरण के प्रति प्रतिक्रिया महामारी आने से पहले ही शुरू हो गई थी, क्योंकि वैश्वीकरण ने विजेता और हारने वाले दोनों को बनाया था। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था इस प्रक्रिया को सभी के लिए विन-विन बनाने के लिए सहयोगात्मक समाधान नहीं दे सकी। यह वास्तव में एक बहुपक्षीय समूह के रूप में जी 20 के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। वैश्वीकरण को वैश्विक दक्षिण सहित सभी के लिए बेहतर और अधिक न्यायसंगत परिणाम देना चाहिए।

विश्व समुदाय के सामने आने वाले कई जोखिमों में से, मुद्रास्फीति में वृद्धि ने मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए ब्याज दरों को पर्याप्त रूप से बढ़ाने और साथ ही कठिन लैंडिंग से बचने के लिए विकास में हानि को कम करने के बीच हर अर्थव्यवस्था में एक जटिल मौद्रिक नीति दुविधा पैदा की है। 2022 की शुरुआत से प्रणालीगत केंद्रीय बैंकों द्वारा आक्रामक मौद्रिक नीति कड़ी करने और इसके परिणामस्वरूप, अमेरिकी डॉलर की वृद्धि ने कई अर्थव्यवस्थाओं को विदेशी ऋण के उच्च शेअर के साथ ऋण संकट के प्रति अत्यधिक संवेदनशील बना दिया है। आईएमएफ[2] के अनुसार, कम आय वाले देशों (एलआईसी) में से 15 प्रतिशत पहले से ही ऋण संकट में हैं, अतिरिक्त 45 प्रतिशत ऋण संकट के उच्च जोखिम में हैं। करीब 25 प्रतिशत उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाएं (ईएमई) भी उच्च जोखिम में हैं। इसके अलावा, वित्तीय स्थितियों में लगातार सख्ती के कारण उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं (ईएमडीई) से पूंजी बहिर्वाह से आरक्षित घाटा, तीव्र मुद्रा मूल्यह्रास और आयातित मुद्रास्फीति दबाव बढ़ गया है। ऐसी स्थिति में, निम्न और मध्यम आय वाले देशों में बिगड़ती ऋण स्थिति से निपटना और बहुपक्षीय ढांचे के तहत आधिकारिक द्विपक्षीय और निजी लेनदारों द्वारा समन्वित ऋण उपाय की सुविधा प्रदान करना हमारी जी 20 अध्यक्षता के तहत प्राथमिकता बन गयी है।

कुछ महीने पहले आसन्न मंदी के बारे में भारी चिंताओं के बावजूद, वैश्विक अर्थव्यवस्था ने वास्तव में अधिक लचीलापन प्रदर्शित किया है, जिससे हार्ड लैंडिंग की संभावना कम हो गई है। बहरहाल, वैश्विक विकास में गिरावट का रुझान है। मुद्रास्फीति के संचालकों में होने वाले संरचनात्मक बदलावों के बारे में भी काफी अनिश्चितता है, जिसमें श्रम बाजार की गतिशीलता से लेकर बाजार शक्ति का संकेंद्रण और कम कार्यक्षम आपूर्ति शृंखला शामिल हैं। समानांतर में, वैश्विक खाद्य, ऊर्जा और अन्य वस्तुओं की कीमतें संबंधित चरम सीमा से कम हो गई हैं और आपूर्ति शृंखला सामान्य हो रही है, जिससे अवस्फीति को प्राप्त करने में मदद मिलनी चाहिए। इसलिए, अधिक संतुलित विश्व आर्थिक व्यवस्था की बहाली जी 20 चर्चाओं में सबसे आगे है। भारत ने वैश्विक विकास को पुनर्जीवित करते हुए बहुपक्षवाद में स्थिरता और विश्वास बहाल करने के लिए एक समावेशी एजेंडा बनाने के महत्व पर जोर दिया है।

एक खंडित वैश्विक शासन व्यवस्था, जैसा कि आज प्रचलित है, ने वैश्विक सार्वजनिक वस्तुओं के प्रावधान को कम करने और आर्थिक कल्याण में कटौती की अगुवाई की है। महामारी के दौरान टीकों तक भेदभावपूर्ण पहुंच और जीवन रक्षक दवाओं के लिए टीकों और प्रौद्योगिकी तक सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करने की अनिच्छा; ईएमई में हरित संक्रमण की गति तेज करने के लिए वित्त और प्रौद्योगिकी तक पहुंच का अपर्याप्त प्रावधान; और कुछ ऋणग्रस्त विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के सामने आने वाले गंभीर तनाव को दूर करने के लिए समय पर लेनदार सहयोग की कमी, ये हाल के उदाहरण हैं। बहुपक्षवाद के प्रति पुन: प्रतिबद्ध होना समय की मांग है और इस संबंध में जी 20 की प्रमुख भूमिका है।

यह भी महत्वपूर्ण है कि जी 20 देश सदस्य देशों में हो रहे जन-केंद्रित परिवर्तनकारी परिवर्तनों पर उचित ध्यान दें और दुनिया को सभी के लिए एक बेहतर स्थान बनाने के लिए उन्हें अपनाएं। आम आदमी के लिए जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, एक-दूसरे के अनुभव से सीखना भविष्य में, वैश्विक आर्थिक

[2] आईएमएफ, विश्व आर्थिक आउटलुक अपडेट - जनवरी 2023।

व्यवस्था का एक नया आयाम होना चाहिए। मैं, हमारे जी 20 अध्यक्षता के तहत ऐसे दो प्रमुख क्षेत्रों पर प्रकाश डालना चाहता हूं: पहला, वित्तीय समावेशन के लिए डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा; और दूसरा, जलवायु परिवर्तन और अधिक समावेशी वैश्विक आर्थिक व्यवस्था प्राप्त करने के लिए न्यूनीकरण।

वित्तीय समावेशन के लिए डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा

जी 20, वित्तीय समावेशन के लिए वैश्विक साझेदारी (जीपीएफआई) के माध्यम से, वैश्विक मंच में वित्तीय समावेशन पर बातचीत की सुविधा प्रदान कर रहा है। गैर-सेवारत एवं वंचित व्यक्तियों और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) पर ध्यान केंद्रित है। भारत गरीबी उन्मूलन और समाज के कमजोर वर्गों के आर्थिक सशक्तिकरण के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए वित्तीय समावेशन के साथ-साथ डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के उपयोग में अपने अनुभव को साझा कर रहा है। भारत अपने विश्व स्तरीय डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे का लाभ उठाकर 'लास्ट-मील कनेक्टिविटी' के मुद्दे को संबोधित करने में अग्रणी रहा है, जिसमें जेएएम (जन-धन, आधार, मोबाइल) त्रिमूर्ति; यूपीआई; डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क (ओएनडीसी); और खाता एग्रीगेटर्स (एए) ढांचा शामिल है। हम वैश्विक रूप से एकीकृत वित्तीय समावेशन पारितंत्र को सक्षम करने में डिजिटल पहचान, डिजिटल भुगतान और डेटा के डिजिटल सहमति-आधारित साझाकरण के महत्व पर भी प्रकाश डाल रहे हैं। इस क्षेत्र में भारत का समृद्ध और सफल अनुभव आम आदमी के जीवन को बेहतर बनाने के मार्गों पर अच्छा मार्गदर्शन प्रदान कर रहा है। आश्चर्य की बात नहीं है कि भारत को हाल ही में, इटली के साथ वित्तीय समावेशन कार्य समूह के लिए वैश्विक साझेदारी के सह-अध्यक्ष के रूप में चुना गया है।

जलवायु परिवर्तन और शमन

जलवायु परिवर्तन अब दूर का खतरा नहीं है। वह यहीं हमारी ओर देख रहा है और दुनिया भर के लाखों जीवन और आजीविका के लिए जोखिम के साथ बढ़ता एक खतरा बना है। दुनिया भर में चरम मौसम की घटनाएं, जैसे बाढ़, सूखा, जंगल की आग, चक्रवात आदि उत्पादन और आपूर्ति शृंखलाओं को बाधित कर सकती हैं और किसी भी समय, कहीं भी आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की कमी निर्माण कर सकती हैं। इस तरह की घटनाएं कीमतों में अचानक वृद्धि पैदा कर सकती हैं जिससे मुद्रास्फीति का दबाव बढ़ सकता है। इसके अलावा, जलवायु परिवर्तन उन क्षेत्रों की उत्पादकता को भी प्रभावित कर सकता है जो प्रकृति पर बहुत अधिक निर्भर हैं, जैसे कि कृषि। उदाहरण के लिए, बढ़ते तापमान और बारिश के पैटर्न में बदलाव के कारण, हाल के वर्षों में फसल की पैदावार कम हो रही है और खाद्यान्न की कीमतें बढ़ रही हैं। जलवायु परिवर्तन का भौतिक प्रभाव, जैसे समुद्र के स्तर में वृद्धि और चरम मौसम की घटनाओं की आवृत्ति और तीव्रता में वृद्धि, बुनियादी ढांचे और संपत्ति को नुकसान पहुंचा सकती है, जिससे व्यवसायों और परिवारों के लिए उच्च लागत हो सकती है। इन सभी कारकों से मुद्रास्फीति में और बढ़ोतरी तथा विकास में कमी आ सकती हैं, जो परिवारों और व्यवसायों की क्रय शक्ति को नष्ट कर सकते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हाल के वर्षों में ऐसी घटनाएं बार-बार हो रही हैं। इसलिए, यह आवश्यक है कि हम अपने ग्रह और उसके निवासियों के भविष्य की रक्षा के लिए ठोस जलवायु कार्रवाई करें।

इस एजेंडे को आगे ले जाने के लिए जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक कार्रवाई और जलवायु वित्त के प्रावधान के लिए नेतृत्व प्रदान करने में, जी 20 देशों की एक बड़ी जिम्मेदारी है। मौसम संबंधी आपदाओं से निपटने में, भारत ने अपने हरित संक्रमण एजेंडे और कुशल आपदा प्रबंधन के लिए क्षमता निर्माण में उल्लेखनीय प्रगति की है। अन्य जी 20 देशों के साथ अपने अनुभव साझा करने से हरित वैश्विक अर्थव्यवस्था के साझा लक्ष्य को हासिल करने के लिए सहयोग की गुंजाइश का पता लग सकता है।

उल्लेखनीय है कि भारत जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक[3] 2023 के अनुसार उच्चतम रैंक वाला जी 20 देश है और विश्व स्तर पर 5वां सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला देश भी

[3] जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक (सीसीपीआई), 2005 से प्रतिवर्ष प्रकाशित होता है, 59 देशों और यूरोपीय संघ के जलवायु संरक्षण प्रदर्शन को ट्रैक करने के लिए एक स्वतंत्र निगरानी उपकरण है, जो वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन का 92 प्रतिशत है। यह जर्मनवॉच, दी न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क द्वारा प्रकाशित किया गया है।

है। यह देखते हुए कि भारत को व्यापक रूप से दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक के रूप में बने रहने की उम्मीद है, हमारी ऊर्जा मांग कई गुना बढ़ सकती है। हमारे लिए चुनौती दोहरी है: एक, ऊर्जा की मांग में अनुमानित वृद्धि को पूरा करना; और दूसरा, जीवाश्म ईंधन से नवीकरणीय ऊर्जा में तेजी से अंतरण।

हाल के वर्षों में बुनियादी ढांचे में बड़े निवेश को देखते हुए हमारे बुनियादी ढांचे की जलवायु प्रूफिंग भी प्राथमिकता रही है। आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन (सीडीआरआई)[4] जैसे वैश्विक मंचों के माध्यम से, भारत इन चुनौतियों से निपटने के लिए वैश्विक प्रयासों को नेतृत्व प्रदान कर रहा है।

हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां जलवायु घटनाओं के कारण, वैश्विक समष्टि-आर्थिक और वित्तीय दृष्टिकोण तेजी से अनिश्चित हो सकता है, और केवल सहयोग की भावना के साथ एक प्रतिबद्ध वैश्विक प्रतिक्रिया आसन्न जोखिम को कम करने में मदद कर सकती है। इस संदर्भ में, यदि हम महत्वाकांक्षी निवल शून्य लक्ष्यों को पूरा करना चाहते हैं तो संतुलित तरीके से शमन और अनुकूलन प्रयासों के लिए जलवायु वित्त को बढ़ाने की आवश्यकता को अच्छी तरह से समझना है। इस प्रयास में बहुपक्षीय विकास बैंकों (एमडीबी) की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्हें ऋण संसाधनों की बढ़ती मांग की पूर्ति, ज्ञान सहायता प्रदान करने और गरीबी में कमी और सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को प्राप्त करने की अपनी पारंपरिक भूमिकाओं को जारी रखते हुए निजी निवेश को उत्प्रेरित करने के लिए विकसित होना चाहिए। इन मुद्दों के समाधान के लिए जी 20 ने एमडीबी को मजबूत करने पर विचार-विमर्श करने के लिए एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया है।

अंत में, मैं अपनी बात समाप्त करते हुए यह कहना चाहता हूं कि अमरीकी बैंकिंग प्रणाली में हाल के घटनाक्रमों ने बैंकिंग क्षेत्र के विनियमन और पर्यवेक्षण की महत्वपूर्णता को सामने ला दिया है। ये ऐसे क्षेत्र हैं, जिनका प्रत्येक देश की वित्तीय स्थिरता को संरक्षित करने पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। विशेष रूप से, अमेरिका में ये विकास विवेकपूर्ण आस्ति देयता प्रबंधन, मजबूत जोखिम प्रबंधन और देयताओं और आस्तियों में टिकाऊ वृद्धि सुनिश्चित करने, आवधिक तनाव परीक्षण करने; और भविष्य में किसी भी अप्रत्याशित तनाव के लिए पूंजी बफर का निर्माण करने के महत्व को बढ़ाते हैं। वे यह भी बताते हैं कि क्रिप्टो मुद्राएं/संपत्ति या इसी तरह के अन्य से, बैंकों के लिए चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक वास्तविक खतरा हो सकता है। रिजर्व बैंक ने इन सभी क्षेत्रों में आवश्यक कदम उठाए हैं। वित्तीय क्षेत्र और विनियमित संस्थाओं के विनियमन और पर्यवेक्षण को उपयुक्त रूप से मजबूत किया गया है। विनियामकीय कदमों में अन्य बातों के अलावा, लीवरेज अनुपात (जून 2019), बड़े एक्सपोजर फ्रेमवर्क (जून 2019), वाणिज्यिक बैंकों में शासन पर दिशानिर्देश (अप्रैल 2021), मानक आस्तियों के प्रतिभूतिकरण पर दिशानिर्देश (सितंबर 2021), एनबीएफसी के लिए स्केल-आधारित विनियामक (एसबीआर) ढांचा (अक्टूबर 2021), माइक्रोफाइनेंस के लिए संशोधित नियामक ढांचा (अप्रैल 2022), शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) के लिए संशोधित विनियामक ढांचा (जुलाई 2022) और शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) के लिए दिशानिर्देश शामिल हैं (सितंबर 2022)।

इसके साथ ही, हाल के वर्षों में आरबीआई की पर्यवेक्षी प्रणालियों को उपायों के माध्यम से काफी मजबूत किया गया है जिसमें वाणिज्यिक बैंकों, एनबीएफसी और यूसीबी के लिए एक एकीकृत और सामंजस्यपूर्ण पर्यवेक्षी दृष्टिकोण शामिल है। ऑन-साइट पर्यवेक्षी कार्य की आवृत्ति और तीव्रता अब संस्थानों के आकार के साथ-साथ जोखिम पर आधारित है। ऑफ-साइट पर्यवेक्षण भी अधिक तीव्र और लगातार हो गया है। हमने पर्यवेक्षित संस्थाओं के वरिष्ठ प्रबंधन और बोर्डों के साथ अपने जुड़ाव को मजबूत किया है। अकेले लक्षणों से निपटने के बजाय अब कमजोरियों के मूल कारण की पहचान करने पर अधिक ध्यान केंद्रित किया गया है। हमने वित्तीय संस्थाओं की निगरानी और आश्वासन कार्यों पर संशोधित दिशानिर्देश भी जारी किए हैं। उन्नत डेटा विश्लेषिकी का उपयोग हमारी पर्यवेक्षी प्रक्रिया को पूरक रहा है। साइबर लचीलेपन को मजबूत करने के लिए, डिजिटल भुगतान सुरक्षा नियंत्रण दिशानिर्देशों के साथ बैंकों के लिए एक व्यापक साइबर सुरक्षा ढांचा जारी किया गया है। हमने पर्यवेक्षकों के

[4] आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन (सीडीआरआई) एक बहु-हितधारक वैश्विक साझेदारी है जो नए के निर्माण का समर्थन करती है और निरंतर विकास को बढ़ावा देने के लिए जलवायु और आपदा जोखिमों के लिए मौजूदा बुनियादी ढांचे प्रणालियों के लचीलेपन को विकसित करती है। भारत एक संस्थापक सदस्य है, और संगठन का मुख्यालय नई दिल्ली में है।

कॉलेज की भी स्थापना की है और हाल के वर्षों में कर्मचारियों की संख्या में काफी वृद्धि की है। आज भारत में हमारे पास एक अच्छी तरह से विनियमित और अच्छी तरह से पर्यवेक्षित बैंकिंग क्षेत्र है। यह एनबीएफसी क्षेत्र और आरबीआई के अधिकार क्षेत्र के तहत आने वाली अन्य वित्तीय संस्थाओं पर भी लागू होगा।

निष्कर्ष

अब मैं यह कहते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं कि भारत ने ऐसे समय में जी-20 की अध्यक्षता संभाली है जब यह एक बार फिर विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है। वैश्विक आर्थिक व्यवस्था को नया रूप देने के लिए रचनात्मक योगदान देने की भारत की क्षमता पर अंतर्राष्ट्रीय विश्वास बढ़ रहा है। हार्ड लैंडिंग की जोखिम दुनिया भर में समाप्त हो गई है, भले ही अवस्फीति की गति वांछनीय से कम बनी हुई है। भू-आर्थिक विखंडन के व्यापक प्रभावों से वैश्विक दृष्टिकोण एवं कम होने से पहले, सहयोग के माध्यम से विश्वास का पुनर्निर्माण और महत्वपूर्ण वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए बहुपक्षीय ढांचे के लिए फिर से प्रतिबद्ध होना आवश्यक हो गया है। हर संकट का समाधान तब हो सकता है जब प्रभावशाली दिमाग एक साथ आते हैं। जैसा कि स्वामी विवेकानंद जी ने एक बार कहा था " ... मन की शक्तियां छितराई प्रकाश की किरणों की तरह हैं; जब वे केंद्रित होती हैं, तो वे जगमगाती हैं"[5]।

धन्यवाद।

[5] स्वामी विवेकानंद के पूर्ण कार्य, खंड 1, अध्याय 1, परिचयात्मक। https://advaitaashrama.org/cw/content.php